MANOHAR PARRIKAR INSTITUTE FOR
DEFENCE STUDIES AND ANALYSES
मनोहर परिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान

बहुपक्षवाद के नए संदर्भों में भारत की 'सॉफ्ट पावर' कूटनीति

ओमप्रकाश दास

भूमिका

आधुनिक विश्व में एक शक्तिशाली राष्ट्र की परिभाषा मज़बूत राजनीतिक नेतृत्व, आर्थिक सम्पन्नता, सैन्य क्षमता, अंतरिक्ष तक पहुंच जैसे शब्दावलियों से मिलकर गढ़ी जाती है। इन शब्दावलियों के समूह में सफल कूटनीतिक प्रयासों और रणनीतिक साझेदारियों की भूमिका भी बेहद निर्णायक होती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दुनिया में किसी राष्ट्र के सामर्थ्य की परिभाषा इस बात पर निर्भर करती है कि कोई राष्ट्र, किसी दूसरे राष्ट्र के व्यवहार को किस हद तक प्रभावित कर सकता है।[1] भू-राजनीति के कई ऐसे पहलू होते हैं, जो किसी देश के लिए वैश्विक स्तर पर अनुकूल स्थितियां और एजेंडे के निर्धारण में प्रभावी लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमिका निभाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जटिल दुनिया में कूटनीतिक रणनीति के ऐसे हिस्से को मोटे तौर पर 'सॉफ्ट पावर' कहा जाता रहा है। साथ ही, 'सॉफ्ट पावर' ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करता है , जो ठोस कूटनीतिक फैसलों को लागू करने की राह को आसान कर देता है। इस वर्ष, भारत G-20 की अध्यक्षता और मेज़बानी कर रहा है, जहां ज्वलंत वैश्विक मुद्दों पर विचार-विमर्श और एक सामूहिक कदम की अपेक्षा की जाती है। मेज़बान देश में, दुनिया की सबसे बड़ी बीस अर्थव्यवस्थाएं पहुंच रही हैं और ये मौका है 'ब्रांड भारत' को सशक्त करने का भी। ऐसे में भारत की छवि, उसकी स्वीकार्यता, समृद्ध सभ्यतागत परंपराएं, लोकतांत्रिक संस्कार, सांस्कृतिक - वैचारिक -प्राकृतिक विविधता जैसे तत्व अपने आप दुनिया की नज़रों में नए सिरे से उभरने लगते हैं।[2]

'सॉफ्ट पावर', कूटनीति और भारत

द्विपक्षीय और बहुपक्षीय कूटनीति में राष्ट्र के हितों को सुरक्षित रखने के लिये सैन्य और आर्थिक साधनों जैसे 'हार्ड पावर'[3] का उपयोग होता रहा है, लेकिन 'सॉफ्ट पावर'[4] के ज़रिए यही लक्ष्य विचारों और मूल्यों के आदान-प्रदान के ज़रिए, किसी मुद्दे या एजेंडे के सहज स्वीकार्यता के निर्माण के लिए होता है। किसी भी देश की 'सॉफ्ट पावर' को जोसफ न्ये ने एक "ऐसे सांस्कृतिक-राजनीतिक मूल्यों की ओर आकर्षण के रूप में बताया हैं जो देश की सीमाओं से परे उसकी पहचान बन जाए। एक ऐसा आकर्षण, जो उस देश को एक वैधानिक और नैतिक स्तंभ की तरह स्वीकार्य बनाता हो।"[5] प्रसिद्ध चीनी राजनयिक, हू शिह ने एक बार कहा था कि "भारत ने अपनी सीमा के पार एक भी सैनिक भेजे बिना 20 शताब्दियों तक सांस्कृतिक रूप से चीन पर विजय प्राप्त की और प्रभुत्व जमाया।"[6] लेकिन आज

भारत 'ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स'[7] में शीर्ष 20 देशों में शामिल नहीं है।[8] 'लेकिन सवाल है कि क्या भारत क़दम उठा रहा है?

बहुपक्षवाद और 'सॉफ्ट पावर'

बहुपक्षीय मंच और संवाद बुनियादी रूप से सामूहिक विकास और सह-अस्तित्व की मूल भावना पर आधारित होते हैं। अपने शुरुआती दौर से ही भारत बहुपक्षवाद के पक्ष में खड़ा रहा है। भारत जलवायु परिवर्तन पर "संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) और अन्य बहुपक्षीय मंचों पर जलवायु वित्त के मुद्दे को उठाने में हमेशा आगे रहा।"[9] यहां उन देशों को भी, भारत ने आवाज दी, जो छोटे द्वीपीय देश हैं और जो वैश्विक तापमान बढ़ने का खामियाज़ा सबसे ज्यादा और जल्दी उठा रहे हैं। यहां तक कि भारत ने G-20 की प्राथमिकताओं को लेकर भी साफ किया है कि "प्राथमिकता जलवायु वित्त की समावेशी और सतत वृद्धि होनी चाहिए।"[10]

बड़े देशों के बीच अपने मुनाफे को सुरक्षित रखने के लिए होने वाले 'ट्रेड वॉर' हो या एक समय संयुक्त राज्य अमेरिका का 'पेरिस जलवायु समझौते' से पीछे हट जाना, यूरोपियन यूनियन पर ब्रेक्जिट जैसा ग्रहण लगना, ये कुछ ऐसी घटनाओं के उदाहरण हैं, "जो बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में बहुपक्षवाद, अपने सार्वभौमिक और गैर-सार्वभौमिक दोनों स्तरों पर सवालों के घेरे में आया है।"[11] ऐसे में भारत वर्षों से इस बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार की वकालत करता रहा है। साथ ही, भारत ने G-20 को लेकर अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट भी किया है। भारत ने स्पष्ट तौर पर "बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार की वकालत की है।"[12]

G-20: मिले सबको आवाज़

दुनिया के कई देश अरबों डॉलर के ऋण–जाल में फंसे हैं साथ ही कई देशों को भुगतान संकट से भी दो चार होना पड़ रहा है।[13] आंकड़े बताते हैं कि "2010 से 2020 के बीच विकासशील देशों का सार्वजनिक ऋण जीडीपी के औसत 40.2 से बढ़कर 62.3 प्रतिशत हो गया है।"[14] पिछली फरवरी (2023) को G-20 की वित्त मंत्रियों की बैठक में भारत ने इन देशों के ऋण मुक्ति के उपायों के मुद्दों को प्रमुखता से रखा।[15] मसलन, नकदी की कमी से जूझ रहे कई अफ्रीकी, लैटिन अमेरिकी और मध्य पूर्व के कई देशों ने अरबों डॉलर के ऋण और परियोजनाओं को लेकर समझौते किए हैं,[16] जिसमें अधिकांश सौदे कभी ज़मीन पर उतर ही नहीं पाए और अगर काम हुआ भी तो ज्यादातर निवेश घाटे का सौदा ही साबित हुए।[17] वही, दूसरी ओर पिछली जनवरी में G-20 की अलग-अलग बैठकों की शुरुआत होने से पहले भारत ने 'वॉयस ऑफ़ ग्लोबल साउथ समिट 2023' की मेज़बानी की, जहां दक्षिणी गोलार्द्ध के कई देशों ने शिरकत की। इसमें विशेषकर एशिया, अफ्रिका और लैटिन अमेरिका के निम्न और मध्यम आय वाले देशों के मुद्दे सामने आए। समिट के दौरान, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र

मोदी ने कहा कि "जहां तक भारत का संबंध है, आपकी आवाज भारत की आवाज है। आपकी प्राथमिकताएं भारत की प्राथमिकताएं हैं।"[18] भारत ने भरोसा दिया कि व्यापक ग्लोबल साउथ की चिंताओं को भारत समझता है और उनके "सभी विचार G-20 के एजेंडे को आकार देने के लिए भारत को प्रेरणा देंगे।"[19] भारत 2023 में G-20 का अध्यक्ष है और अध्यक्ष के पास शिखर सम्मेलन तक अलग-अलग मुद्दों पर एजेंडा के निर्धारण में बड़ी भूमिका होती है। ऐसे में भारत ने ये स्पष्ट संदेश दिया कि वो उन देशों के साथ खड़ा है जिनकी आवाज और चिंताएं वैश्विक स्तर पर जगह नहीं पाते हैं।

विरासत और आगे की राह

ब्रिटिश राज के भारत में पतन के बाद से ही, भारत दुनिया भर में वर्चस्वशाली और साम्राज्यवादी शक्तियों के सामने एक प्रेरणा स्रोत की तरह स्थापित हो गया। 1947 में भारत की स्वतंत्रता ने दुनियाभर में राष्ट्रवादी आंदोलनों में नई जान फूंक दी। भारत ने दुनिया के दमित हिस्से को औपनिवेशिक ताकतों से लड़ने के लिए एक सैद्धांतिक हथियार और नैतिक शक्ति दिए। इसके बाद तो साम्राज्यवादी शक्तियों के पांव उखड़ने लगे, विशेषकर अफ्रीका महाद्वीप में सभी अफ्रीकी उपनिवेश 1965 तक साम्राज्यवादी शक्तियों से मुक्त हो गए।[20] कुछ ऐसा ही दक्षिण पूर्व एशियाई में म्यांमार और इंडोनेशिया में भी देखा गया। वहीं, दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद के खिलाफ आंदोलन को "भारत ने नीतिगत रूप से इसका समर्थन किया।"[21] आधुनिक विश्व में शीत युद्ध के दौरान "भारत ने 'नॉन अलाइंड' आंदोलन के ज़रिए कई देशों की वर्चस्ववादी शक्ति से मुक्ति की प्रेरणा दी। वहीं, भारत की उपनिवेशवाद-विरोधी और साम्राज्यवाद-विरोधी आदर्श और नीतियों ने विदेश नीति में दुनिया के पीड़ित देशों के साथ वैचारिक साझापन का अध्याय लिखा।"[22]

भारत अपनी बौद्ध कूटनीति, धार्मिक पर्यटन, साहित्य – संगीत, फिल्मों, सॉफ्टवेयर उद्योग, योग, आयुर्वेद, मेडिकल पर्यटन जैसे अलग-अलग क्षेत्रों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में 'सॉफ्ट पावर' की क्षमताओं को खंगालता रहा है । शायद यही कारण भी है कि भारत G-20 की "32 अलग-अलग कार्यक्षेत्रों की 200 से ज्यादा बैठकें देश के 50 से अधिक शहरों में आयोजित कर रहा है।"[23] जिसका मकसद है भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविधता को दुनिया के सामने और विशेषकर G-20 के प्रतिनिधियों को अनुभव करने का अवसर देना।

श्रीलंका के आर्थिक दिवालियापन हो,[24] वर्ष 2015 में नेपाल में आया भूकंप हो,[25] 2023 में तुर्किए में आया विनाशकारी भूकंप हो, दुनियाभर में भारतीय शांति सैनिकों की सराहनीय भूमिका हो, अफगानिस्तान का पुनर्निर्माण हो, भारत वैश्विक बंधुत्व की नैतिक कसौटी पर खरा उतरता रहा है। वैश्विक मंचों पर वर्ष 2023 को 'बाजरा वर्ष' के रूप में मनाने का प्रस्ताव हो[26] या 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस'[27] की वैश्विक स्वीकार्यता, भारत ने 'सॉफ्ट पावर' की एक नई ऊर्जा का अहसास कराया है। आज भूमंडलीकृत दुनिया में वर्चस्ववादी ताकते अपने हितों की रक्षा के लिए सक्रिय हैं, ऐसे में जब दुनिया एक बार फिर से दो ध्रुवों में बंटने की कगार पर पहुँचती दिख रही है। ऐसे में आज भारत एक

नैतिक शक्ति और वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरा है, जहां समस्याओं के समाधान के लिए दुनिया उसकी ओर देख रही है। ऐसे में G-20 एक अवसर लेकर आया है, जहां भारत 'सॉफ्ट पावर' को नए संदर्भों में फिर से स्थापित कर सकता है।

Keywords: G-20, 'सॉफ्ट पावर', विकासशील देश, बहुपक्षवाद और ग्लोबल साउथ

---

[1] Nicolas Blarel, **"India: The Next Superpower?: India's Soft Power: From Potential to Reality?"**, London School of Economics and Political Science IDEAS reports - special reports, SR010, 2012.

[2] D. Mahapatra, **"From a Latent to a 'Strong' Soft Power? The Evolution of India's Cultural Diplomacy"**, *Palgrave Commun* 2, 16091, 2016.

[3] Colin S. Gray, **"Hard Power and Soft Power: The Utility of Military Force as an Instrument of Policy in the 21st Century"**, Strategic Studies Institute, US Army War College, 2011.

[4] Ibid.

[5] Joseph S. Nye, Jr., **"Public Diplomacy and Soft Power"**, *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 616, March 2008, pp. 94–109.
[6] Kamal Sheel, **"Hu Shih and 'The Indianisation of China': Some Comments on Modern Chinese Discourses on India"**, *China Report*, Vol. 50, No. 3, pp. 177–188.

[7] **"Global Soft Power Index",** Brand Finance.

[8] Amit Sarwal, **"India Jumps while Australia Slips One Spot in Global Soft Power 2023 Ranking"**, *The Australia Today*, 3 March 2023

[9] **"India Has Taken Lead to Raise the Issue of Climate Finance at International Forums"**, Press Information Bureau, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, 28 July 2022.

[10] **"In G-20 Presidency Meeting, India Seeks Reforms in Multilateral Institutions"**, Press Trust of India, 26 November 2022.

[11] Amrita Narlikar, **"The Malaise of Multilateralism and How to Manage It"**, Observer Research Foundation, 23 January 2020.

[12] **"In G-20 Presidency Meeting, India Seeks Reforms in Multilateral Institutions"**, Press Trust of India, 26 November 2022.

[13] David Shambaugh, ed., *China and the World,* Oxford University Press, New York, 2020, p. 133.

[14] Daniel Munevar, **"A Debt Pandemic: Dynamics and Implications of the Debt Crisis of 2020"**, Briefing Paper, European Network on Debt and Development, March 2021.

[15] Michelle Jamrisko, **"G-20 Host India Taps Soft Power as It Champions New World Order"**, *The Economic Times,* 21 February 2023.

[16] David Shambaugh, ed., *China and the World*, no. 13, p. 301.

[17] "चीन-अफ्रीका सहयोग पर फोरम (Forum on China–Africa Cooperation – FOCAC) में चीन लगातार आर्थिक समझौतों को साल दर साल तेज़ी से बढ़ाता रहा है। वहीं, पहले चीन और द कम्युनिटी ऑफ लैटिन अमेरिकन एंड कैरेबियन स्टेट्स फोरम (Forum of China and the Community of Latin American and Caribbean States - CELAC) के तहत 2015-

2019 सहयोग योजना की घोषणा की गई, जिसमें चीन ने अगले दशक में लैटिन अमेरिका में $250 बिलियन डॉलर निवेश करने का लक्ष्य रखा है।", as mentioned in David Shambaugh, ed., *China and the World,* no. 13, p. 301.

[18] **"Text of PM's Remarks at Opening Session of Voice of Global South Summit 2023"**, Press Information Bureau, Prime Minister's Office, Government of India, 12 January 2023.

[19] **"वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के लीडर्स सत्र के समापन के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का समापन भाषण"**, PM INDIA, Government of India, 13 January 2023.

[20] Dinesh D'Souza, **"What's So Great About America"**, Regnery Publishing, Washington, D.C, 2002, pp. 58–59.

[21] J. Peter Pham, **"India's Expanding Relations with Africa and their Implications for US Interests"**, *American Foreign Policy Interests*, Vol. 29, No. 5, 2007, pp. 341–52.

[22] David M. Malone, **"Soft Power in Indian Foreign Policy"**, *Economic & Political Weekly*, Vol. 46, No. 36, 3 September 2011.

[23] **"G-20 and India's Presidency"**, Press Information Bureau, Ministry of External Affairs, Government of India, 10 December 2022.

[24] Ganeshan Wignaraja, **"India Mulls Aid in Sri Lanka's Hour of Need"**, East Asia Forum, 19 July 2022.

[25] **"Indian Air Force Continues to Provide Relief to Stranded Persons of Earthquake hit Nepal"**, Press Information Bureau, Ministry of Defence, Government of India, 13 May 2015.

[26] **"International Year of Millets (IYM) 2023 Kick Starts with Focussed Activities Being Undertaken by Central Ministries, State Governments and Indian Embassies"**, Press Information Bureau, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Government of India, 1 January 2023.

[27] **"International Day of Yoga 21 June"**, United Nations.